SHRI T.R. BAALU: The recommendation of the Ministry of Environment is to use jute bags manufactured out of textile materials, and so on. As far as plastic materials are concerned, we have banned the use of plastic bags only up to a thickness of 20 microns.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhdev Singh Libra. He is not here.

SHRI K.M. KHAN: Sir, I would like to know from the hon. Minister, keeping in view the hazardous effects of the plastic bags, how the Government proposes to create awareness amongst the distributors and the public. Do you have any plan to bring forward a legislation for banning the usages of plastic bags in the country?

SHRI T.R. BAALU: Sir, we have already banned the usage of plastic bags up to a thickness of 20 microns.

Convention on Rights of the Child

*72. DR. T.SUBBARAMI REDDY:
SHRIMATI SHABANA AZMI:†

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the country's first periodic report on the implementation of the Convention on the Rights of the Child observed that India lacked separate legislation to deal with such cases;

(b) if so, whether the report prepared by the Department of Women and Child Development is to be submitted to the UN Committee on the Rights of the Child;

(c) if so, what are the other recommendations of the report; and

(d) whether Government are considering any legislation to deal with child abuse cases?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Shabana Azmi.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) It is not correct to say that Indian Laws are not adequate to meet the country's obligations under the Convention on the Rights of the Child (CRC). State Parties to the CRC are required to furnish periodic reports on its implementation. The first such Periodic Country Report was prepared in 2001 by this Ministry, following a consultative process and was submitted to the UN Committee on the Rights of the Child.The Report spells out constitutional provisions, laws, policies and programmes being implemented in India with reference to various provisions of the CRC. The Country's laws are consistent with its obligations under the CRC.

(d) The Law Commission of India in their 172nd Report have recommended comprehensive changes in law to safeguard children from sexual abuse and exploitation. This Report is receiving the attention of the Justice Malimath Committee on criminal justice reforms.

SHRIMATI SHABANA AZMI: Sir, I am deeply disappointed with the reply because it is a very deliberate attempt to evade giving a clear answer. Now, the Children's Code 2000, under the Charmanship of Justice Krishna Iyer, was presented to the Prime Minister, on 14th November, 2000, in the presence of the hon. HRD Minister who had promised to look into it. I would like to know what is the status of the Children's Code 2000. Since It is a comprehensive code of children's rights, having integrated every aspect of all child-centric laws, would the Government consider having a comprehensive plan of action, based on a child's right approach, to implement the CRC, which India has ratified? Merely bringing amendments to the Child Labour Act of 1986 will not solve the problem. The household enterprises, Government institutions and training centres are no longer exempt from prohibitions on employing children; and the coverage is expanded to include agricultural and other informal sectors. The Act, for instance, does not define the term "hazardous". Children's right activists claim that any work that prevents a child from going to school should be considered hazardous. So, there is a lot needs toJie done. What is the Government doing in this regard? Thank you.

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैंने अपने उत्तर में बहुत स्पष्ट कहा है कि कुछ मामलों में भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है । उसमें खास तौर पर जो चाइल्ड ऐब्यूज़ है, उस सिलसिलें में कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने की उन्होंने सिफारिशें की है । उस पर मलीमथ कमेटी विचार कर रही है । यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। जहां तक यह कहा जाता हैं कि भारत सरकार इसमें क्या कर रही हैं, सरकार ने काफी कानूनों के तहत इस बारे में विचार किया है। लोगों से आम राय ली जा रही है, राज्य सरकारों से बात की जा रही है । इसके अलावा हमने चार्टर आर्फ चिल्ड्रन्स राइट्स तैयार किया है । भारत के बच्चों के लिए कमीशन बनाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर चिल्डन की सिफारिश की है जिस पर प्लानिंग कमीशन से वार्ता हो रही है । उनके सुझावों के आधार पर विचार चल रहा है ।

श्री मती शबाना आज़मी : सर, चिल्ड्रन्स कोड-2000 का क्या स्टेटस हैं ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : उस स्टेटस पर भी विचार हो रहा हैं । उसके आधार पर भी जब आपके सामने रिपोर्ट आएगी, आयोग आएगा...

SHRIMATI SHABANA AZMI: Sir, the fact is that Children's Code, 2000 is a very comprehensive legislation, ita т?R* dfru&rii ~&& ^ n»i<iqi ^t" ^RTTI Sir, it is a totally comprehensive legislation. It looks at every signle law concerning children. So, there is no point in bringing any amendments and separate laws, because ultimately they will not solve the problem.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, मुझे उत्तर देने की आज्ञा हैं या नहीं । मेरा उत्तर पूरा होने से पहले ही माननीय सदस्या...

श्री सभापति : मैंबर्स यह चाहते हैं कि बाल मजदूरी जल्दी से जल्दी रूके ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : इस संबंध में मैंने बताया है कि सारी मिनिस्टरीज़ से हमारी राय हो रही है । मैंने उल्लेख किया है कि जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आती है – बाल श्रम से संबंधित केवल हमारा ही मंत्रालय नहीं है – विभिन्न मंत्रालय से उस पर बात करनी पड़ती है । श्रम मंत्रालय से बात करनी पड़ती है, गृह मंत्रालय से बात करनी पड़ती हैं राज्य सरकारों से बात करनी पड़ती है । हमने उसको प्रसारित कर दिया, उस पर बातचीत चल रहीं हैं । जो विधि आयोग ने रिपोर्ट दी, उस पर मलीमथ कमेटी बैठी हुई है । हमने स्वंय चिल्ड्रन्स राइट्स के लिए चार्टर और...

श्री सभापति : आपने सब कुछ किया है ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सब कुछ कर रहें हैं, वह प्रक्रिया में हैं ।

श्री सभापति : बाल मजदूरी रुकनी चाहिए ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : बाल मजदूरी जरूर रूकेगी और बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं।

*73. [77?e *Questioner (Shri A. Vijaya Raghavan) was absent. For answer vide pages* 48-49 *infra].*

*74. *[The Questioner (Shrimati Vanga Geetha) was absent. For answer vide pages* 49-50 *infra].*

रेलवे में टक्कर रोधी यंत्र

*75. **श्री सी.ओ पॉलोस** : †

श्री पीं. के. माहेश्वरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉकण रेलवे ने टक्कर-रोधी यंत्रों को विकसित किया है:,

(ख) क्या इसकी कार्य कुशलता को परखने के लिए परीक्षण किए गए हैं :,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :,

(घ) क्या इस संयंत्र को अभी तक किसी रेल मार्ग पर लगाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं:,

(ङ) क्या रेलवे इस यंत्र को सभी मार्गो पर लगाने का विचार रखता है: और

(च) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रारंभिक फील्ड परीक्षणों के बाद इस यंत्र की उपयुक्तता की जाचं करने के लिए 15.5.2002 से 19.1.2003 तक उत्तर रेलवे के जालंधर – अमृतसर खंड पर विस्तृत फील्ड परीक्षण

---

† सभा में यह प्रश्न श्री सी.ओ. पॉलोस द्वारा पूछा गया।